सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बकाया अंतर शाखा प्रविष्टियां

2220. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंतर शाखा बकाया प्रविष्टियां छः माह की अवधि के भीतर नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार बैंकवार बकाया प्रविष्टियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार छः माह के भीतर अंतरशाखा बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के लिए क्या प्रयास कर रही है और इस संबंध में निगरानी कार्य की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अन्तर शाखा समाधान खातों में समाधान न की गई प्रविष्टियों के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

(I) शाखाओं के स्तर पर दैनिक शाखा विवरणों के संकलन में देरी/कमियां जो अंतर शाखा समाधान का मूल निवेश्य हैं;

(II) पंचिंग में खामियां

(III) प्रधान कार्यालय में अंतर-शाखा समाधान कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण; और

(IV) पुराने रिकार्डों का उपलब्ध न होना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.1.1995 की स्थिति के अनुसार बकाया प्रविष्टियों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1993 तक की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को कवर करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर शाखा समाधान खातों में 65.55 लाख प्रविष्टियां बकाया थी।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं: उच्च मूल्य वाली प्रविष्टियों को अलग किये जाने को प्राथमिकता देना, विशेषकक्ष/कृतिक बल की स्थापना करना, समय सीमा का विनिर्देशन इत्यादि। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि उनके निदेशक मंडल को छमाही में या थोड़े अंतरालों में, यदि आवश्यक हो, अंतर-शाखा समाधान में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार

2221. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विकास संघ ने हाल ही में भारत को आर्थिक सुधार की धीमी रफ्तार के संबंध में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये हैं?

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी, नहीं। शिष्टमंडलों ने संरचनात्मक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उल्लेखनीय सफलता का मूल्यांकन किया और भविष्य में तीव्र अभिवृद्धि के लिए अच्छे-लक्षणों सहित, 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र अभिवृद्धि प्राप्त की। तथापि, यह नोट किया गया कि आगे के लिए कार्यसूची अत्यधिक आवश्यक है।

(ग) और (घ) भारतीय शिष्टमंडल ने संकेत दिया कि सरकार राजकोषीय समायोजन और सुधार कार्यक्रम में निरन्तर उन्नति करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। आर्थिक सहायताओं को विवेकपूर्ण स्तर पर रखा गया और राजकोषीय विधाक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कर व्यवस्था में अतिरिक्त सुधार इस आशय के प्रमाण थे।

किसानों की वित्तीय आवश्यकताएं

2222. **श्री आस मोहम्मद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की पूर्ण संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है ताकि वे प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन पाने के लिए पूंजी निवेशों का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) योजना आयोग के कार्य दल ने आठवीं योजनावधि के दौरान, कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण का पूर्वानुमान लगाया था, जो निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
1992-93	7,619	7.369	14,988
1993-94	8,898	8,650	17,548
1994-95	10,534	10,143	20,677
1995-96	12,457	11,665	24,122
1996-97	15,041	13,414	28,455

कृषकों की उत्पादन ऋण की आवश्यकता वित्त की मात्रा के आधार पर मंजूर की जाती है। फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्रा, स्थानीय रूप मे उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त की इस मात्रा को वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी होती है और इसे कीमतों, निविष्टयों के स्तर, खेती की कुल लागत, कुल उपज, वापसी अदायमी की क्षमता आदि के आधार पर पुन: नियत किया जाता है।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋणों का कम से कम 18% कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिए जाने ऋण के प्रवाह मे विशिष्ट ओर महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से बैंकों से विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन पर वे सुविधापूर्वक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं तथा उनसे तदनुसार अपनी कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादन के वास्ते समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए जो किसान कतिपय मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें उनकी मिश्रित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध है जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तथा उनको भी दी जाती है जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन जो फसल उगाने के साथ डेरी, कुक्कुट पालन आदि और या अन्य कृषि-तर कार्य जैसे संबद्ध कार्य करते हैं और जिनका पिछले दो वर्षों में बैंक/ऋणकर्त्ता खाते का संतोषजनक रिकार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे मछली पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलाजी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के कार्यों का वित्तपोषण करें।

गुजरात में महिला सहकारी बैंक

2223. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कार्यरत महिला सहकारी बैंकों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से ऐसे और बैंक खोलने संबंधी कोई निवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) इस समय गुजरात में 7 महिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं जिनका जिला वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

जिले का नाम	महिला सहकारी बैंको की सं.
अहमदाबाद	3
बड़ोदरा	1
भावनगर	1
सूरत	1
बलसाड़	1
	7

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को गुजरात में महिला सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करना है बशर्ते कि, प्रस्ताव भविष्य में अपेक्षित सम्भाव्यताओं को पूरा करता हो और अर्थक्षमता की सम्भाव्यता हो। महिलाओं द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक शेयर पूंजी और सदस्यता संबंधी स्थापना के समय के मानदण्डों में कतिपय छूट प्रदान की गई है।

Drug Trafficking in Tamil Nadu

2224. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily Hindu dated 7th November, 1994 about the drug trafficking and seizure of heroin in Tamil Nadu;

(b) whether it is a fact that there are